पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः आषाढ़ 22, 1944

बुधवारः 13 जुलाई 2022

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीपीएसयू के नॉन-ऑफिशियल निदेशकों को 'आत्मनिर्भर भारत' साकार करने के प्रयास द्वारा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया

उन्हें सतर्क रक्षक करार दिया जो रचनात्मक सुझावों के माध्यम से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए डीपीएसयू का मार्गदर्शन कर सकते हैं

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) के नॉन-ऑफिशियल निदेशकों (एनओडी) को 'रक्षा में आत्मनिर्भरता' हासिल करने की दिशा में सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया। रक्षा मंत्री रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा नई दिल्ली में 13 जुलाई 2022 को आयोजित अपनी तरह की पहली कार्यशाला के दौरान डीपीएसयू के सीएमडी और एनओडी को संबोधित कर रहे थे। श्री राजनाथ सिंह ने बल देकर कहा कि देश आत्मनिर्भरता की दिशा में एक परिवर्तनकारी दौर का सामना कर रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना को साकार करने के लिए सक्रिय और सामूहिक रूप से प्रयायरत है।

श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत रक्षा उपकरणों/प्लेटफार्मों की अधिग्रहण प्रक्रिया के सरलीकरण सहित आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों को सूचीबद्ध किया;

समायोजित दिशानिर्देशों में लचीलापन; एफडीआई सीमा में स्वचालित मार्ग के तहत 74% और सरकारी मार्ग के तहत 100% तक की वृद्धि; लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण; इनोवेशन्स फोर डिफेंस इक्सीलेंस (आईडीईएक्स) पहल का शुभारंभ और रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग में वृद्धि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक रक्षा उत्पादन के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डीपीएसयू 70-80 प्रतिशत के योगदान के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और सीएमडी तथा एनओडी से मिलकर काम करने का आग्रह ताकि ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के बीच स्थान बना सकें।

रक्षा मंत्री ने एनओडी को डीपीएसयू और एमओडी की एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया, जो न केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि काम सरकार की नीतियों के अनुसार किया जाए। सुझाव देने में स्वतंत्रता को उनकी सबसे बड़ी ताकत के रूप में पहचानते हुए, उन्होंने एनओडी को सरकार के उद्देश्यों के अनुसार प्रबंधन के प्रदर्शन की जांच करने; सकारात्मक निवेश और रचनात्मक समीक्षा के माध्यम से निर्णय लेने के लिए मूल्य वर्धन करने और डीपीएसयू, सरकार तथा राष्ट्रों के हितों की रक्षा करने का आह्वान किया।

श्री राजनाथ सिंह ने एनओडी को सतर्क रक्षक करार दिया जो रणनीति, निष्पादन, जोखिम प्रबंधन, संसाधनों, प्रमुख नियुक्तियों, सीएसआर, सतत विकास और डीपीएसयू के संचालन के मानकों पर कड़ी नजर रखते हैं। उन्होंने डीपीएसयू को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करने में एनओडी के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला और उनसे निजी क्षेत्र में प्रचलित सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को शुरू करने और नीति निर्माण में सूक्ष्म दृष्टि और मार्गदर्शन साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एनओडी को अधिक से अधिक अनुसंधान एवं विकास के लिए डीपीएसयू को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें प्रत्यक्ष जोखिमों के लिए प्रेरित करना चाहिए। रक्षा मंत्री ने हाल के वर्षों में डीपीएसयू के उत्कृष्ट

प्रदर्शन की सराहना की और सीएमडी को एनओडी के सुझावों पर उचित कार्रवाई करने का आह्वान किया।

रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने अपने समापन भाषण में डीपीएसयू के सीएमडी से उन एनओडी के सामर्थ्य का उपयोग करने का आह्वान किया जिनके पास निजी क्षेत्र के कौशल, अनुभव, स्वतंत्रता और ज्ञान का उचित संतुलन है। उन्होंने कहा कि एनओडी कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों को बढ़ावा दे सकते हैं और डीपीएसयू की विश्वसनीयता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी दक्षता में सुधार हो सकता है। उन्होंने एनओडी से प्रबंधन एवं शेयरधारकों के हितों के बीच संतुलन बनाने और निर्णय लेने में योगदान देने का आग्रह किया।

रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने एनओडी की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों पर प्रकाश डालते हुए उनसे आत्मनिर्भरता की दिशा में डीपीएसयू के प्रयासों पर अधिक जोर देने का आग्रह किया। उन्होंने उद्योग जगत, शिक्षा जगत और स्टार्ट-अप के साथ सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ उन्हें सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों/उपकरणों को विकसित करने तथा निर्यात बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देने का आह्वान किया। उन्होंने डीपीएसयू को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एनओडी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने एक दिशानिर्देश तैयार करने का आह्वान किया जो वर्ष 2047 तक 20 भारतीय रक्षा विनिर्माण कंपनियों को दुनिया के शीर्ष 100 रक्षा उद्यमों में शामिल कर सके।

कार्यशाला का उद्देश्य एनओडी को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में संवेदनशील बनाना और डीपीएसयू के प्रदर्शन में सुधार करने में उनकी मदद करना था। एनओडी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बोर्ड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक स्वतंत्र निर्णय लेने में मदद करते हैं, बोर्ड एवं प्रबंधन के प्रदर्शन के मूल्यांकन में एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण लाते हैं; कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण मानकों की सुविधा; हितधारकों के हितों को संतुलित करने और कंपनी द्वारा हरित प्रौद्योगिकियों और संसाधन संरक्षण प्रथाओं को अपनाने में प्रोत्साहित करते हैं

एबीबी/डीएस